

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

81 / 2019
11.11.2019

भजन पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी खजूरिया तहसील व जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला—टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार टोंक दिनांक 27.09.2019 मिसल नम्बर 191 / 2019

उपरिस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 21.12.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह एवं खसरा नम्बर 109 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 290/रु. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और ना ही मौका का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवायी गई है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है और ना ही भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक को तैयार की गई का अंकन भी पटवारी रिपोर्ट में नहीं है। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट स्वतंत्र गवाह के समक्ष तैयार




जिला कलेक्टर
टोंक

नहीं की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

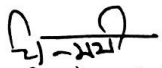
अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा 104 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह एवं खसरा नम्बर 109 रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की और से पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 104 मे से रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह एवं खसरा नम्बर 109 मे से रकबा 1 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर तिल की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 675/2019 निर्णय दिनांक 27.02.2019 से भूमि से बेदखल किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 27.09.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी-मोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक